

मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन, 26 मई 2015 – दिल्ली

घोषणा पत्र

देश की सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ सभी क्षेत्रों और सेवा प्रतिष्ठानों के स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच के बैनर तले आयोजित मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन, वर्तमान केंद्रीय सरकार के मजदूर विरोधी, जन विरोधी और कार्पोरेट पक्षी कार्रवाईयों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस अवधि में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों को उनके अधिकार और लाभों से वंचित करने और नियोजकों को "रखो और हटाओ" (हायर एंड फायर) के निरंकुश अधिकार से सशक्त बनाने के लिए सभी श्रम कानूनों में संशोधन के साथ-साथ देश के रणनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रेलवे, रक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में असीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के लिए हमलावर तरीके से आगे बढ़ाने में सरकार अत्यधिक व्यस्त है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी अंधाधुंध परिवर्तन द्वारा किसानों के भूमि का अधिकार और खेत मजदूरों के अजीविका के अधिकार को जर्बदस्त तरीके से दबाने और समाप्त कर देने जैसा प्रतीत होता है।

श्रम कानूनों में अंधाधुंध परिवर्तन को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य और कुछ नहीं बल्कि मजदूरों के अपार बहुमत को सभी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर ट्रेड यूनियन अधिकारों को समाप्त करना है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन अन्वय मुद्दों के साथ सख्ती से श्रम कानूनों का कार्यान्वयन और सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही हैं, परंतु यह सरकार श्रम कानूनों में प्राप्त सभी अधिकारों के दायरे से उन्हें दूर करके सभी कार्यस्थलों पर बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति पैदा करने के उद्देश्यों से कार्य कर रही है। कर्मचारी भविष्यनिधि (इपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (इएसआई) स्कीमों को ऐच्छिक(आप्शनल) बनाने के प्रस्ताव का भी उद्देश्य संगठित क्षेत्रों में उपलब्ध बुनियादी सामाजिक सुरक्षा ढांचा वाले पीएफ और इएसआई को विनष्ट या तहस-नहस करना है। विशाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मूर्ख बनाने के उद्देश्यों से बिना कोई कोष आवंटन किये और कार्यान्वयन तंत्र या व्यवस्था तैयार किये बगैर फिर से उसे पुनर्नामित कर नये आवरण बांधने का कार्य किया जा रहा है। सरकार मीडिया में मुद्रास्फीति कम होने के बड़े-बड़े दावों के अलावा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत रोकने और रोजगार सृजन करने में कोई कदम नहीं उठाया है। जन-वितरण प्रणाली को सर्वव्यापी बनाने की बजाय उस पर सीधा लाभ स्थानांतरण के माध्यम से सरकार इसको तबाह करने की कोशिश कर रही है जिसका परिणाम आम आदमी पर फिर से कहर के रूप में होगा।

एक साल के अंदर ही राज्य सरकारें वर्तमान केंद्रीय सरकार के समर्थन से बुनियादी श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन ला रही हैं, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका मजदूर (विनियम व उन्मूलन) अधिनियम, कारखाना अधिनियम, फैक्टरी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) अधिनियम में संशोधन करके 'रखो और हटाओ' (हायर एंड फायर) लागू कर दिया है, जो 71 फीसदी कारखानों को कारखाना अधिनियम के दायरे से बाहर कर देगा और 50 मजदूरों तक नियोजित करने वाले ठेकेदारों को मजदूरों के प्रति किसी भी जवाबदेही से आजाद कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कारखाना अधिनियम में संशोधन पेश किया है जिसमें कारखाना निबंधन हेतु मजदूरों की सीमा दो गुणा बढ़ाने, लघु उद्योग (सेवा शर्तों का विनियमन) विधेयक का प्रस्ताव लोक परिसंधि में डाला है, जिसमें 40 मजदूरों तक नियोजित करने वाले कारखानों पर 14 प्रमुख श्रम कानून लागू नहीं होने का प्रावधान है। कानूनों के मिश्रण के आवरण में लाये गये मजदूरी विधेयक श्रम संहिता और औद्योगिक संबंध विधेयक श्रम संहिता ट्रेड यूनियनों के निबंधन को पूरी तरह असंभव बनाने का प्रयत्न है और छंटनी और बंदी करने के लिए नियोजक वर्ग को पूरी तरह आजादी देना है। ट्रेड यूनियनों से किसी तरह का परामर्श किये बिना इन विधेयकों को लोक परिधि में डाला जाना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के त्रिपक्षीय परामर्श से संबंधित कन्वेंशन 144 के प्रावधानों का उल्लंघन है। कर्मचारी भविष्य निधि और एमपी अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा (इएसआई), जो मजदूरों के कल्याण के लिए दो अच्छी व जांची परखी स्कीम है, को भी अंततः पूरी तरह तहस-नहस करने के लिए कुटिल डिजाइन के साथ ऐच्छिक बनाने का संशोधन लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को श्रम कानूनों में राजस्थान आकृतिक (मॉडेल) का अनुसरण करने हेतु पत्र लिखा है। इन सभी संशोधनों का मतलब है 90 प्रतिशत श्रमशक्ति को श्रम कानून कार्यान्वयन दायरे से अलग करने के साथ ही मजदूरों को निचोड़कर शोषण करने हेतु नियोजकों को इजाजत देना।

43वें, 44वें और 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, ठेका मजदूरों को भी नियमित मजदूरों की तरह समान वेतन और लाभ देने तथा केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों में कार्यरत उन तमाम श्रमिकों जैसे आंगनवाड़ी, मिड-डे-मील (मध्याह्न भोजन), आशा, पारा शिक्षकों आदि को विद्यमान लाभों के साथ 'मजदूर' का दर्जा देने के संदर्भ में आम सहमति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के प्रति सरकार के पूर्णतः अक्रमण्यता पर भी कन्वेंशन निराशा व्यक्त करता है। इसके विपरीत सरकार बेरहमी से गरीब लोगों के कल्याण वाली उन सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के बजट आवंटन में सरकार ने बेरहमी पूर्वक कटौती

की है। अत्यंत दुख के साथ यह भी अंकित (नोट) किया गया है कि वर्तमान सरकार संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के 12 सूत्री मांगपत्रों की लगातार उपेक्षा कर रही है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी की उत्तेजक स्थिति पर रोक लगाने, श्रम कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन, बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ठेकेदारी प्रथा रोकना, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी जो 15000 रुपये से कम नहीं हो की गारंटी और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों सहित सभी के लिए सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा लाभ और पेंशन आदि शामिल हैं। मांगों में ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन 45 दिन में अनिवार्य रूप से करने और आइएलओ कन्वेंशन 87 और 98 को अनुमोदित करने की मांगें भी सम्मिलित हैं।

रक्षा, बीमा, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति की सरकारी पहल और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों जिसमें पेट्रोलियम एवं वित्त क्षेत्र भी शामिल हैं, में विनिवेश के लिए सरकार की आक्रामक पहल, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ विशाल आम जनता के लिए नुकसानदेह है, का राष्ट्रीय कन्वेंशन निंदा करता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में लाये गये अंधाधुंध परिवर्तन जिसमें किसानों की जमीन जबरिया अधिग्रहित करने की स्वीकृति और खेत मजदूरों की अजीबिका को खतरों में डालने का परिणाम निकलेगा, उसकी भी कन्वेंशन निंदा करता है। कन्वेंशन बहुत गहरी चिंता जताता है कि झूठे व मनगढ़ंत मुकदमों में फंसाये गये मारुति के मानेसर प्लांट के 147 मजदूर पिछले 2 वर्षों से जेलों में जबरन बंद रखे गये हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोकिया, पेरम्बूर की बंद इकाई को चालू करने के प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी उसे बेच देने के हाल के फैसलों से सरकार का श्रमिकों को संरक्षण देने से इंकार का रूख प्रदर्शित होता है। सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हाथों कमर्शियल कार्यों के लिए पहले ही खोल दिया है। बैंकिंग उद्योग में भी सरकार जन विरोधी बैंकिंग क्षेत्र सुधार को आगे बढ़ाना चाहती है जबकि कार्पोरेट के यहां बकाया विशाल खराब ऋण राशि (एनपीए) वसूलने के लिए कोई कारगर कारवाई की पहल नहीं कर रही है।

कन्वेंशन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त परिषद् सदस्यों (जेसीएम) के 23 नवंबर 2015 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के फैसले का समर्थन करता है। कर्मचारियों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन और एकजुटता की कार्रवाईयों के रूपों का फैसला उपर्युक्त चरण में इस मंच द्वारा लिया जायेगा। सरकार की नीतियों के विरुद्ध हड़ताल करने वाले कोयला, परिवहन, डाक और दूरसंचार (टेलीकॉम) मजदूरों का भी यह कन्वेंशन अभिनंदन करता है।

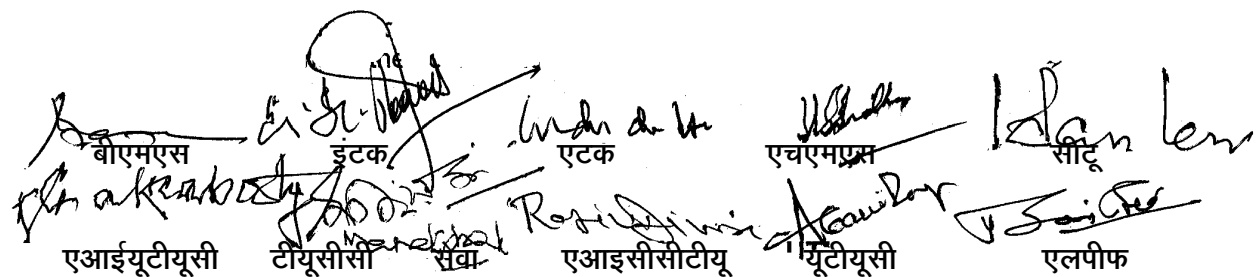
कन्वेंशन केंद्र सरकार से मांग करता है कि श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बनाने वाले संशोधनों को तुरंत बंद करे। कन्वेंशन यह भी मांग करता है कि क्रमवार भारतीय श्रम सम्मेलन के आम सहमति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए तत्काल पहल करें और देश के सभी ट्रेड यूनियन आंदोलनों के लंबे समय से लंबित मांगों के प्रति भी सकारात्मक रूख अपनाएं। कन्वेंशन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का विनिवेश और रक्षा, बीमा, रेलवे आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति उदारता के अंधाधुंध अभियान पर विराम लगाये। इस क्षेत्र में चलाई जा रही आर्थिक नीतियों की दिशा को मोड़ने के बदले प्रमुख बंदरगाहों और डाक सेवा आदि का निगमीकरण (कार्पोरेटाइजेशन) की केंद्र सरकार की पहल की भी कन्वेंशन निंदा करता है, जिसमें संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को धाराशाही कर दुर्गति में डाल दिया है और श्रमजीवी जनता पर बहुत बुरा असर डाला है।

कन्वेंशन सभी ट्रेड यूनियनों, सभी क्षेत्र के फेडरेशनों को आह्वान करता है कि अपनी एकता को व्यापक बनाते हुए जमीनी स्तर पर अपनी एकता को मजबूत करें और सरकार के निर्लज्ज मजदूर विरोधी, जन विरोधी नीतियों को रोकने और प्रतिरोध करने हेतु देशव्यापी संयुक्त आंदोलन के लिए तैयार रहें और उसकी तैयारी हेतु सर्वसम्मति से निम्न कार्यक्रम स्वीकार करता है।

1. जून और जुलाई माह में राज्य, जिला और उद्योग स्तर पर, जहां-जहां संभव हो, संयुक्त कन्वेंशन और अभियान आयो. जित कर और आम जनों से मजदूर आंदोलन में सहयोग लेने की पहल करे।

2. 2 सितंबर, 2015 को अखिल भारतीय आम हड़ताल की जायेगी।

राष्ट्रीय कन्वेंशन सभी ट्रेड यूनियनों और आम श्रमजीवी जनता का आह्वान करता है कि अपनी अलग-अलग सम्बद्धता के बाद भी एकताबद्ध होकर उपरोक्त कार्यक्रम को असरदार ढंग से सफल करें।



 बीएमएस इटक एटक एचएमएम सीटू

 एआईयूटीयूसी टीयूसीसी सेवा एआईसीसीटीयू यूटीयूसी एलपीफ

और बैंक, बीमा, रक्षा, रेलवे केंद्रीय /राज्य सरकार कर्मचारियों और अन्य सेवा प्रतिष्ठानों की फेडरेशनों

NATIONAL CONVENTION OF WORKERS, 26.5.2015, DELHI

DECLARATION

This National Convention of Workers being held under the banner of joint platform of all the Central Trade Unions of the country along with independent national federations of all sectors and service establishments expresses deep concern over anti worker, anti-people and pro-corporate actions of the present Govt. at the Centre in pursuance of the policy of globalisation. During this period the Govt. has been over-busy in amending all labour laws to empower the employers with unfettered rights to “hire and fire” and stripping the workers and trade unions of all their rights and benefits besides aggressively pushing through almost unlimited FDI in strategic sectors like Railways, Defence and Financial Sector. Also, through sweeping changes in the existing Land Acquisition Act, farmers’ right to land and agri-workers’ right to livelihood are being sought to be drastically curbed and curtailed.

The Govts’ aim in aggressively pushing through sweeping changes in labour-laws is nothing but to push out overwhelming majority of workers out of the coverage of all labour laws and to drastically curb the trade union rights. The CTUs had besides other issues raised the issue of strict enforcement of labour laws and universal social security but this Govt. is doing away with all rights-components in all the labour laws aiming at creating conditions of bonded labour in all the workplaces. EPF and ESI schemes are proposed to be made optional which is also aimed at demolishing the PF and ESI schemes dismantling the basic social security structures available to the organized sector. And for the vast unorganized sector workers, old schemes are being repackaged and renamed, without providing for funds and implementation-machinery/network with a view to befool the people. The Govt. has not taken any step to curb price rise of essential commodities and to generate employment except making tall claims of containing inflation in the media. On universalising public distribution system, the Govt. is trying to scuttle it through Direct Benefit Transfer resulting further squeeze on the common people.

During the year with the support of the present Govt, various state governments have brought about drastic anti-workers changes in basic labour laws viz., Industrial Disputes Act, Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, Factories Act and Apprenticeship Act, Trade Unions Act etc introducing “hire & fire”, throwing more than 71% of factories out of coverage of Factories Act and making all contractors employing up to 50 workers free from any obligation towards workers. The Central Govt. on its part has introduced amendments to Factories Act raising doubly the limit of workers for registration of factories, put in public domain the proposals for new Small Factories (Regulations of Service conditions) Bill which prescribes that major 14 labour laws will not apply to factories employing upto 40 workers. Labour Code on Wages Bill and Labour Code on Industrial Relations Bill which under the cover of amalgamation seek to make registration of unions almost impossible, making retrenchment and closure almost free for the employers class. These bills have been put in public domain without consulting the trade unions thereby violating the provisions of ILO Convention 144 on Tripartite Consultation. Amendments have also been brought in EPF & MP Act and ESI Act to make it optional with a sinister design to finally demolish the two time-tested statutory schemes for the workers. The Prime Minister’s office has written to the Chief Secretaries of States to follow Rajasthan Model in labour laws. All these amendments are meant to exclude 90% of the workforce from application of labour laws thereby allowing the employers to further squeeze and exploit the workers.

The Convention also expresses dismay over the Govt’s total inaction in implementing the consensus recommendations of 43rd, 44th and 45th Indian Labour Conferences on formulation of minimum wages, same wage and benefits as regular workers for the contract workers and granting status of workers with attendant benefits to those employed in various central govt schemes like anganwadi, mid-day-meal, ASHA, para-teachers etc. On the contrary, the Govt drastically curtailed budget allocations to all those centrally sponsored schemes meant for poor peoples’ welfare. It is also noted with utter dismay that the present government is also continuing to ignore the

twelve point demands of entire trade union movement pertaining to concrete action to be taken for containing price-rise and aggravating unemployment situation, for strict implementation of labour laws, halting mass scale unlawful contractorisation, ensuring minimum wages for all of not less than Rs 15000 per month with indexation and universal social security benefits and pension for all including the unorganized sector workers, etc. The demands also include compulsory registration of Trade Unions within 45 days and ratification of ILO Conventions 87 and 98. Even the legislations passed by Parliament on the issue of Street Vendors is not being implemented appropriately.

The National Convention also denounced the retrograde move of the Govt. in hiking/allowing FDI in Defence, Insurance, Railways and other sectors and also its aggressive move for disinvestment in PSUs including Oil and financial sector aiming at total privatisation which will be detrimental to the interests of the national economy, national security as well as mass of the common people. The National Convention also condemned the sweeping change sought to be brought in Land Acquisition Act permitting forcible acquisition of land from the farmers and putting in jeopardy the livelihood of agricultural workers. It is disgusting to note that 147 workers of Maruti-Suzuki at Manesar are being forced to languish in Jail for more than two years on false and fabricated charges. It is unfortunate that even after the assurance of Prime Minister to revive the closed NOKIA Sriperumbudur unit, the recent decision to sell it out demonstrates Government approach to deny protection to workers. The coal sector has already been opened for commercial operations by private sector. In the banking industry also, the govt. wants to push their anti-people banking sector reforms while no effective action is being taken to recover the huge bad loans (NPA) from the Corporate Sector.

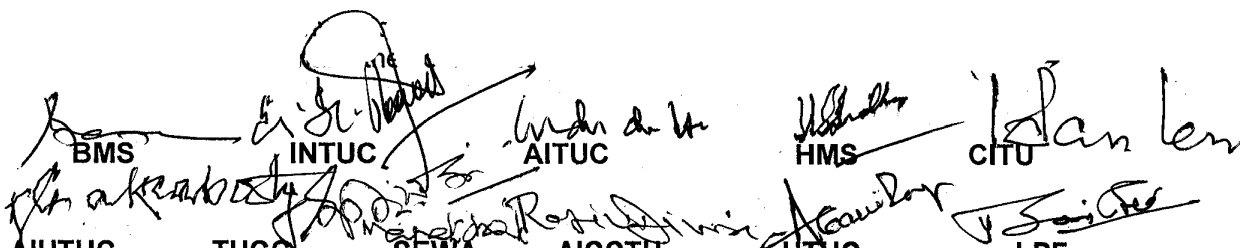
The Convention supports the decision of the constituents of JCM of Central Govt. employees to go for indefinite strike from 23rd November, 2015 and will decide at appropriate stage the form of solidarity action to be taken. The Convention also congratulates coal, postal, transport and telecom workers for their strike against policies of the Govt.

The Convention demands upon the Central Govt. to stop forthwith the process of making retrograde amendments to the labour laws. The Convention also demands immediate steps to implement the consensus recommendations of successive Indian Labour Conferences and also positive response to long pending demands of the entire trade union movement of the country. The Convention urges the Central Govt. to desist from mindless drive for disinvestment in CPSUs and liberalising FDI in defence, insurance, Railways etc. and the convention also condemns the Govt. move of corporatization of major ports and postal services etc. The Convention urges the Govt. to reverse the direction of the ongoing economic policy regime which has landed the entire national economy in distress and decline affecting the working people most.

The Convention calls upon all the trade unions, federations across the sectors to widen and consolidate the unity at the grass-root level and prepare for countrywide united movement to halt and resist the brazen anti-worker and anti-people policies of the Govt and in preparation to the same undertakes unanimously the following programme:

- 1) **Joint conventions and campaigns during June-July in state, district and industry level wherever possible and taking initiative to involve common people in support of workers struggle**
- 2) **ALL INDIA GENERAL STRIKE ON 2ND SEPTEMBER 2015**

The National Convention calls upon the trade unions and working people irrespective of affiliations to unite and make the countrywide General Strike a massive success.



BMS **INTUC** **AITUC** **HMS** **CITU**

AIUTUC **TUCC** **SEWA** **AICCTU** **UTUC** **LPF**

and All India Federations of Banks, Insurance, Defence, Railways, Central/State Govt. Employees and other Service Establishments